सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन बंद होना सुनिश्चित करें : सीएस

उल्लंघन करने वाले सभी विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा उद्योग विभाग सबसे पहले इन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों का उत्पादन बंद करना सुनिश्चित करें, तभी इनके उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि उल्लंघन करने वाले सभी विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्य सचिव राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए अभियान चलाया जाए और आम जन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

- **'सख्ती के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि लोग इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक हों तथा स्वतः प्रेरणा से इसका इस्तेमाल बंद करें'**

उन्होंने कहा कि लोगों को इस अभियान से जोड़कर ही इसे पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि पर्यावरण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा उद्योग विभाग आपसी समन्वय से इस प्रतिबंध को सफलता से लागू करें। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए सख्ती के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि लोग इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक हों तथा स्वतः प्रेरणा से इसका इस्तेमाल बंद करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद ही प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग बढ़ावा मिलेगा तथा और भी बेहतर विकल्प सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से स्टार्टअप्स इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वन विभाग सचिव बी प्रवीण ने प्रतिबंध लागू करने के लिए कार्ययोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट सैल का गठन भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माताओं, विक्रेताओं और स्टॉक धारियों की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नम्बर की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के निपटान तथा दूसरे राज्यों से प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट के आवागमन पर रोक के लिए तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिये आम-जन को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, रीको, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, गृह विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग से अधिकारियों को प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त करने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है और वसूल की जा सकने वाली जुर्माना राशि भी तय कर दी गयी है।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, रीको, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, गृह विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों ने वीसी के जरिये भाग लिया।

सोमवार से फिर मंत्री करेंगे पीसीसी में जनसुनवाई

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बार फिर से जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू होगा। राज्यसभा चुनाव के चलते कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की वजह से सभी मंत्री भी बाड़ाबंदी में चले गए थे। राज्यसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के चलते के विरोध कार्यक्रम में करीब 10 दिन तक राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में आना-जाना रहा था। इस कारण से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब करीब 5 सप्ताह के बाद एक बार फिर जनसुनवाई शुरू होगी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 4 जुलाई से मंत्रिमण्डल के सदस्यों की ओर से सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जनसुनवाई की जायेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों एवं अभ्यावेदनों का रिकॉर्ड रखा जायेगा तथा प्रकरणों के निस्तारण की जानकारी मंत्रीगणों से प्राप्त की जायेगी।

जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत 4 जुलाई को राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं ऊर्जा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी की ओर से जनसुनवाई की जायेगी।

वेदों से प्रेरणा लेकर जीवन को समृद्ध किया जा सकता है : मिश्र

राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृत अकादमी की ओर से तैयार वैदिक पोस्टर्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के शिक्षा एवं कला, संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला भी मौजूद थे।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को राजभवन में राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा तैयार वैदिक सूक्त आधारित सात पोस्टर्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेद की भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर जीवन को समृद्ध और संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने वेद में आए विचारों को पोस्टर्स के जरिए जन-जन तक पहुंचाने का भी आव्हान किया।

प्रदेश के शिक्षा एवं कला-संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने राज्यपाल मिश्र को बताया कि वैदिक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और वैदिक ज्ञान के आमजन में प्रचार-प्रसार हेतु राजस्थान संस्कृत अकादमी और राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा चारों वेदों की जनोपयोगी वैदिक सूक्ति आधारित 7 पोस्टर्स तैयार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन पोस्टर्स में अथर्ववेद आधारित सूक्ति 'धरती हमारी मां है, हम उसके पुत्र हैं, भूमि सत्य पर टिकी है', सामवेद के 'तुम स्वराज्य का सम्मान करो', ऋग्वेद के 'जुआ मत खेलो, खेती करो', 'वेद ज्ञान भारत की रक्षा करता है' के साथ अर्थर्ववेद की पर्यावरण संबंधी एवं यजुर्वेद की 'मीठी वाणी बोलने' संबंधी सूक्तियां चित्रों के साथ प्रकाशित की गयी है।

इससे पहले उन्होंने राज्यपाल मिश्र को संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित साहित्य प्रदान कर, पुष्प तथा सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

डी.बी. गुप्ता ने की राज्यपाल से मुलाकात

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजभवन में मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल मिश्र को सूचना आयोग द्वारा जनहित में त्वरित किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।

राज्यपाल मिश्र ने सूचना आयोग द्वारा लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे, विशिष्ट कैम्प लगाकर आम जन को राहत प्रदान करने के निर्णयों की सराहना की। राज्यपाल मिश्र को मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी.गुप्ता ने बताया कि राज्य सूचना आयोग द्वारा विशिष्ट अदालत शिविरों में सूचना से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कोर्ट लगाने के साथ राज्य सूचना आयोग ने न्यायालय संबंधी डाक जैसे नोटिस, समन और निर्णय आदि संबंधित व्यक्ति को स्पीड पोस्ट से भिजवाने की भी पहल की है। उन्होंने बताया कि जन हित में आयोग परिसर में विशिष्ट अदालत शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई शुक्रवार को

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 89 नए संक्रमित मिले, इससे पहले गुरूवार को 112 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है। इस दौरान 89 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस बीच राज्य में इस बीमारी से एक और मरीज की मौत हो गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन रिकवरी में सुधार होने से एक्टिव केस घटकर 920 रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 9 जिलों में 89 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरूवार को 112 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में आज 43 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 16, बीकानेर में 11, अजमेर में 7, उदयपुर में 4, अलवर में 3 चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में 2-2 और नागौर में 1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 24 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। राज्य में जून के महीने 2677 संक्रमित मिले। वहीं 8 लोगों की मौत हुई है।

- **जयपुर में सर्वाधिक 43 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है।**
- **प्रदेश में जून के महीने 2677 संक्रमित मिले जबकि 8 लोगों की मौत हुई है।**

प्रदेश में शुक्रवार को भी नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान 98 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 920 रह गए हैं। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा 391 मामले जयपुर में है। उधर प्रदेश में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी करोना से मौत का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान जयपुर में इस बीमारी से एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि राज्य में अब तक करोना से 9566 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 7-7 नए संक्रमित जगतपुरा व वैशाली नगर में मिले हैं। इसके अलावा मानसरोवर में 4, सी-स्कीम, शास्त्री नगर व सोड़ाला में 3-3, दुर्गापुरा, झालाना डूंगरी व मालवीय नगर में 2-2 तथा अजमेर रोड, गलता गेट, जवाहर नगर, कानोता, खातीपुरा, प्रताप नगर, सिरसी रोड़, टोंक रोड़ और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 1 मरीजों का एड्रेस गलत मिलने पर उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। इस बीच जिले में केवल 48 रोगी ठीक हुए हैं।

डॉ. मोहनराव भागवत दो जुलाई से राजस्थान प्रवास पर

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत 2 जुलाई से 10 जुलाई तक राजस्थान के प्रवास पर रहेंगे। उत्तर-पश्चिम (राजस्थान) क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश ने बताया कि डॉ. भागवत का 2 जुलाई को प्रातः 10:40 बजे जयपुर आगमन होगा। दोपहर तक वे भारती भवन में ठहरेंगे, इसी दिन दोपहर 2:30 बजे चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे और चूरू में रात्रि विश्राम करेंगे। 3 जुलाई को प्रातः 9 बजे चूरू से रतनगढ़ पहुंचेंगे और प्रातः 10 से 12 बजे तक रतनगढ़ गोलच्छा ज्ञान मंदिर में तेरापंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से वार्ता करेंगे। इसी प्रकार दोपहर 12 बजे रतनगढ़ से चूरू के लिए प्रस्थान कर चूरू में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 04 से 10 जुलाई तक झुंझुनू में रहेंगे और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। प्रांत प्रचारक मुख्य बैठक 7 से 9 जुलाई तक रहेगी।

टेलीकॉम कंपनियों ने कर दी शहर की सड़कें खोखली?

मानसरोवर में वी.टी.रोड पर शुक्रवार को 2 जगह सड़क धंसी, बड़ा हादसा टला

- **पिछले दिनों शिप्रापथ पर 900 एमएम की सीवरेज लाइन में लिकेज का कारण भी एयरटेल-जीओ कंपनी की भूमिगत केबल्स का बताया गया था, यहां धंसी 40 फीट रोड पर अभी तक यातायात सुचारू नहीं हो पाया है**

जयपुर (कासं)। मानसून की हल्की सी बारिश ने राजधानी जयपुर की सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। शुक्रवार को मानसरोवर के वीटी रोड पर अचानक दो जगह सड़क धंस गई। गनीमत रही इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। प्रत्यदर्शियों के अनुसार करीब 5-6 फीट चौड़ा और 8 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया हैं।

सूचना मिलने पर पुलिस और मानसरोवर नगर निगम जोन से टीम मौके पर पहुंची और बैरिकेट लगाकर रूट डायवर्ट किया। इससे पहले भी पिछले दिनों मानसरोवर में ही शिप्रापथ पर द्वारकाधीश गार्डन के पास 40 फीट लंबी सड़क धंस गई थी। यहां सीवरेज लाइन टूटने के कारण धंस सड़क पर अब तक यातायात सुचारू नहीं हो सका। इस लाइन में लिकेज का कारण भी सीवरेज लाइन के नजदीक एयरटेल-जीओ कंपनी की भूमिगत केबल्स डालने को बतया गया था।

अब शुक्रवार को वीटी रोड पर दो जगह सडक़ धंसने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर में जगह-जगह एयरटेल-जीओ, एसीटी समेत कई टेलीकॉल कंपनियां फाइबर केबल डालने का काम रही है, इन लाइनों को भूमिगत बिछाने के चक्कर में सड़कों को कमजोर कर दिया गया हैं। इसके बावजूद नगर निगम और जेडीए प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि दोनों विभागों को केबल बिछाने के बाद सडक़ की जांच करनी होती है, ताकि किसी तरह की कमी रहने पर उसे तुरंत ठीक किया जा सके। नगर निगम और जेडीए प्रशासन टेलीकॉम कंपनियों को केबल बिछाने की परमिशन देता हैं।

कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश मेहरचंद, प्रमोद, संदीप कुमार, सत्येन्द्र कुमार, महिपाल, नरेन्द्र कुमार और सतवीर की जमानत याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें मौजूदा अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दी जाए। इस पर अदालत ने आरोपियों को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देते हुए अर्जियों को खारिज कर दिया है।

इस दौरान राज्य के एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले ही उसके पेपर आउट कर उन्हें बड़ी धनराशि में अन्य लोगों को बेचान किया है। आरोपियों ने परीक्षा से पहले पेपर आउट करने का गंभीर अपराध किया है। इसलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि चिड़ावा की स्पेशल पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर परीक्षा से पहले ही बेचे जा रहे हैं और महिपाल व प्रमोद पूनिया के पास पेपर हैं।

जन्मदिन पर राज्यपाल को राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने बधाई दी

जयपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने व्यक्तिशः फोन पर दी अपनी बधाई और शुभकामना में मिश्र के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी बताते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए मंगलकामना की है। राज्यपाल मिश्र के जन्मदिन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी व्यक्तिशः फोन कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्हें प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता आदि और भी बहुत से लोगों ने बधाई दी।

पीएचईडी पर लगाया 16 हजार रुपए हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने पानी के चालू मीटर को बंद बताकर ज्यादा राशि का बिल जारी करने को सेवा दोष करार देते हुए पीएचईडी विभाग पर 16 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

वहीं पीएचईडी को निर्देश दिया है कि वह नवंबर 2021 से जनवरी 2022 के बिल की राशि 352 रुपए व अंडर प्रोटेस्ट जमा करवाई राशि 1766 रुपए को परिवादी के आगामी बिलों में समायोजित करें और मीटर रीडिंग लेने वाले व बिल बनाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह व सदस्य सीमा शार्दुल ने यह आदेश जवाहर नगर निवासी अनुज माथुर के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा कि उसने विभाग से पानी का कनेक्शन ले रखा है, लेकिन विभाग बिल जारी करने में लगातार अनियमितताएं बरत रहा है। मीटर रीडर ने मीटर को नोट वर्किंग दिखाया है, जबकि वह चालू है। इसके अलावा एक बिल में मीटर को अघरेलू श्रेणी में दर्शा रखा है, जबकि वह घरेलू श्रेणी में आता है। परिवादी ने विभाग के अफसरों से संपर्क कर उन्हें अनियमितता की जानकारी दी, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा कनेक्शन कटने की धमकी के कारण उसे अंडर प्रोटेस्ट ज्यादा बिल राशि जमा करवानी पड़ी।

शहरों में सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों का नियमन कर पट्टे देने की तैयारी में जुटी सरकार?

नगरीय निकायों की सिवायचक जमीन और हाऊसिंग बोर्ड द्वारा मुआवजा देकर अधिग्रहित की गई जमीनों पर बसी कॉलोनियों को पट्टे देने के आदेश दिये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने

जयपुर (कासं)। राज्य में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य छूने के लिए गहलोत सरकार अब सरकारी जमीनों पर बसी कॉलोनियों के पट्टे भी देने की तैयारी में है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि 13 दिसंबर 2013 तक सृजित हो चुकी ऐसी कॉलोनियां, जिनके भूखंड़धारियों का रिकॉर्ड व ले-आउट प्लान संबंधित नगरीय निकायों के पास पहले से मौजूद है, सिर्फ उन्हें पट्टा मिलेगा। जल्द ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन आएगी। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन की आवंटन दर 300 वर्गमीटर तक के भूखण्ड और कॉलोनी में राजकीय भूमि होने पर आरक्षित दर आवासीय में से जो भी कम हो, उसकी 10 प्रतिशत रकम लेकर की जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि निकायों को हस्तांतरित सिवाय चक जमीन के साथ-साथ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा अधिग्रहित की गई जमीनों पर कब्जा करके बसाई गई कॉलोनियों को भी पट्टे मिलेंगे।

- **मंत्री धारीवाल का कहना है कि 13 दिसंबर 2013 तक सृजित हो चुकी ऐसी कॉलोनियां, जिनके भूखंड़धारियों का रिकॉर्ड व ले-आउट प्लान संबंधित नगरीय निकायों के पास पहले से मौजूद है, सिर्फ उन्हें पट्टा मिलेगा**
- **300 वर्गमीटर तक के भूखंड एवं कॉलोनी में सरकारी जमीन, आरक्षित दर अथवा आवासीय में जो कम होगा, उसकी 10 प्रतिशत राशि पर दी जायेगी**
- **यूडीएच मंत्री ने कहा जो प्रकरण एम्पावर्ड कमेटी में न रखने हो, उन्हें महापौर-सभापति के बजाय मुख्य नगरपालिका अधिकारी निपटाएंगे, हर सप्ताह में 2 दिन होगी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक**

दरअसल गुरूवार देर शाम यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने करीब 7 घंटे तक प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर मैराथन बैठक ली थी। इसमें यूडीएच सलाहकार जी.एस.संधू से लेकर प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, जेडीए कमिश्नर रवि जैन, सचिव उज्जवल राठौड़, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ह्रदयेश शर्मा, मुख्य नगर नियोजक आर.के.विजयवर्गीय और सलाहकार एचएस संचेती मौजूद रहे।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का मुख्य फोकस सरकारी जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन को लेकर रहा। उन्होंने अफसरों को साफ कहा कि पिछले साल सरकारी जमीनों पर पट्टे देने पर रोक लगा दी थी, लेकिन नये निर्देशों के मुताबिक इन जमीनों के पट्टे दो। ऐसी सिवाय चक जमीन, जो राजस्व रिकॉर्ड में निकाय के नाम दर्ज है या नहीं है, लेकिन वहां आबादी बस चुकी है। जिन जमीनों का अधिग्रहण निकाय और हाऊसिंग बोर्ड ने करके मुआवजा कोर्ट में जमा करवा दिया है या भू-मालिक को दिया है। ऐसी सभी कॉलोनियों के पट्टे दिये जाएंगे। हालांकि शर्त होगी कि ऐसी कॉलोनियां जो 13 दिसम्बर, 2013 तक सृजित हो चुकी है या भूखण्डधारियों-आवासधारकों का रिकॉर्ड व ले-आउट प्लान संबंधित निकाय के पास पूर्व से ही उपलब्ध हो। धारीवाल ने एम्पावर्ड कमेटी में न रखे जाने वाले प्रकरणों को सुलझाने का अधिकार भी महापौर-सभापति को न देकर मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह में दो दिन एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हो। कृषि भूमि पर बसी ऐसी कॉलोनियां, जहां 60 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है और लोग बस चुके है और वहां 20 फीट की रोड है। ऐसी कॉलोनियों में केवल सर्वे के आधार पर पट्टे दिये जाएंगे।

धारीवाल का कहना है कि मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग, सार्वजनिक ट्रस्ट या किसी धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थान अथवा वक्फ बोर्डए रेल्वे बाउण्ड्री सीमा के अन्तर्गत भूमि, नदी नाले बहाव क्षेत्र, डूब क्षेत्र, जलिय निकाय में आने वाली भूमि राष्ट्रीय, राज्य उच्च मार्ग की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत भूमि, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कानून के अन्तर्गत आवासीय-व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन-नियमन नहीं किया जा सकेगा।

रवि वासवानी ने शिवसेना का दामन थामा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान शिवसेना ने रवि वासवानी युवा नेता के नेतृत्व में सैंकड़ों युवाओं को राजापार्क सोडाला के युवाओं के साथ शिवसेना की सदस्यता देकर शिवसेना में जोड़ा गया और उज्ज्वल मंगलमय जीवन की मंगलकामना की। राज्य प्रमुख ललित सक्सेना ने बताया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुए धोखे के बाद अब शिवसेना राजस्थान में जमीनी स्तर पर कार्य करेगी और शिवसेना को राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करेगी। रवि वासवानी को जल्द ही जयपुर में जिला कार्यकारिणी के लिए मनोनीत किया जाएगा। रवि वासवानी जागरूक होकर युवाओं के साथ एकजुट होकर शिवसेना को समर्पित रहेंगे।

एलआईसी 15 जुलाई तक कर सकता है आईईवी का निर्धारण

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय अन्तर्निहित मूल्य (आईईवी) का निर्धारण 15 जुलाई तक कर सकता है। निगम द्वारा 30 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूर्व में इसका निर्धारण 31 मार्च तक किया जाना था लेकिन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ और समय लग सकता है। एक बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद और अपेक्षित अनुमोदन के बाद इस संबंध में निगम द्वारा आवश्यक सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाएगा।

'नरेन्द्र मोदी जन-कल्याणकारी नीतियों से विजय संकल्प तेलंगाना-2023 को पूरा करेंगे'

जयपुर। भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आज तेलंगाना सम्पर्क अभियान के तहत करीमनगर विधानसभा क्षेत्र के मंडल, मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संवाद किया।

डॉ. पूनिया ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 8 वर्ष की जनकल्याणकारी उपलब्धियों, भाजपा के तेलंगाना मिशन 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 के विजय संकल्प, संगठनात्मक संरचना तथा जनहित सहित तेलंगाना सरकार के विरूद्ध इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर रणनीति पर चर्चा की।

- **डॉ. सतीश पूनिया ने करीमनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से किया संवाद**

उन्होंने कहा कि करीमनगर सहित पूरे तेलंगाना में भाजपा के राष्ट्रवाद के विचार की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है, साथ ही नरेन्द्र मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से यहां की जनता खुश है और केन्द्र की योजनाओं का सीधा लाभ गांव-गरीब के घर तक पहुंच रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया के तेलंगाना दौरे के दौरान उमड़े लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं केन्द्र की जनहितैषी नीतियों से तेलंगाना विजय संकल्प 2023 को पूरा करेंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 विजय संकल्प को प्रचण्ड बहुमत के साथ फिर से हासिल कर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।

डॉ. पूनिया 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रदेश भाजपा इकाई के संगठनात्मक कार्य व आगामी कार्यों का प्रस्तुतिकरण देंगे।